

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ **The first few years in the life of independent India were full of challenges. Some of the most pressing ones concerned national unity and territorial integrity of India. We begin the story of politics in India since Independence by looking at how three of these challenges of nationbuilding were successfully negotiated in the first decade after 1947.**

➤ आज्ञाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज्ञाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया:

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

- **Freedom came with Partition, which resulted in large scale violence and displacement and challenged the very idea of a secular India.**
- **The integration of the princely states into the Indian union needed urgent resolution.**
- **The internal boundaries of the country needed to be drawn afresh to meet the aspirations of the people who spoke different languages.**
- आज़ादी मिली लेकिन देश का बँटवारा भी हुआ। बँटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई; लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी थी।
- देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना ज़रूरी था।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएँ अलग-अलग थीं। लोगों की आकांक्षाओं का खयाल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा-रेखाएँ फिर से तय करनी थीं।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

Challeng for the new nation

At the hour of midnight on 14-15 August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was the famous 'tryst with destiny' speech that you are familiar with.

नए राष्ट्र की चुनौतियाँ

सन् 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' या 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' के नाम से जाना गया।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

This was the moment Indians had been waiting for. You have read in your history textbooks that there were many voices in our national movement. But there were two goals almost everyone agreed upon: one, that after Independence, we shall run our country through democratic government; and two, that the government will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged groups. Now that the country was independent, the time had come to realise the promise of freedom.

हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। बहरहाल, दो बातों पर सबकी सहमति थी—पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास खयाल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

This was not going to be easy. India was born in very difficult circumstances. Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947. Freedom came with the partition of the country.

यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन् 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बँटवारे के साथ।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation.

सन् 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल-पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ Three Challenges

Broadly, independent India faced three kinds of challenges. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united, yet accommodative of the diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. Its people spoke different languages and followed different cultures and religions. At that time it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. The partition of the country appeared to prove everyone's worst fears. There were serious questions about the future of India:

➤ तीन चुनौतियाँ

मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियाँ थीं। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बँधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग-अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग-अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

Would India survive as a unified country? Would it do so by emphasising national unity at the cost of every other objective? Would it mean rejecting all regional and sub-national identities? And there was an urgent question: How was integration of the territory of India to be achieved?

क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ़ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए?

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **The second challenge was to establish democracy. You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. These features ensure that the political competition would take place in a democratic framework. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. The challenge was to develop democratic practices in accordance with the Constitution**

➤ दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढाँच के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार-बरताव चलन में आएँ।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ **The third challenge was to ensure the development and wellbeing of the entire society and not only of some sections. Here again the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. The Constitution also set out in the Directive Principles of State Policy the welfare goals that democratic politics must achieve. The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and**

➤ तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ़ ठ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बरताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक-सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने 'राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों' के अंतर्गत लोक-कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ Partition: displacement and rehabilitation

On 14-15 August 1947, not one but two nation-states came into existence – India and Pakistan. This was a result of ‘partition’, the division of British India into India and Pakistan. The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history textbooks. According to the ‘two-nation theory’ advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two ‘people’, Hindus and Muslims. That is why it demanded Pakistan, a separate country for the Muslims. The Congress opposed this theory and the demand for Pakistan. But several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British role

➤ विभाजन : विस्थापन और पुनर्वास

14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र-भारत और पाकिस्तान-अस्तित्व में आए। ऐसा ‘विभाजन’ के कारण हुआ; ब्रिटिश इंडिया को ‘भारत’ और ‘पाकिस्तान’ के रूप में बाँट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भू-भाग को रेखांकित करते हुए सीमा-रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि ‘हिंदू’ और ‘मुसलमान’ नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की माँग की। कांग्रेस ने ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ तथा पाकिस्तान की माँग का विरोध किया। बहरहाल, सन् 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए; कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश-शासन की भूमिका जैसी कई बातों का ज़ोर रहा। नतीजतन, पाकिस्तान की माँग मान ली गई।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ Process of Partition

Thus it was decided that what was till then known as 'India' would be divided into two countries, 'India' and 'Pakistan'. Such a division was not only very painful, but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India.

➤ विभाजन की प्रक्रिया

फ़ैसला हुआ कि अब तक जिस भू-भाग को 'इंडिया' के नाम से जाना जाता था उसे 'भारत' और 'पाकिस्तान' नाम के दो देशों के बीच बाँट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फ़ैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके 'पाकिस्तान' के भू-भाग होंगे और शेष हिस्से 'भारत' कहलाएँगे।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **The idea might appear simple, but it presented all kinds of difficulties. First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. There were two areas of concentration, one in the west and one in the east. There was no way these two parts could be joined. So it was decided that the new country, Pakistan, will comprise two territories, West and East Pakistan separated by a long expanse of Indian territory. Secondly, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Khan Abdul Gaffar Khan, the undisputed leader of the North Western Frontier Province and known as 'Frontier Gandhi', was staunchly opposed to the two-nation theory. Eventually, his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with**

➤ यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह कि 'ब्रिटिश इंडिया' में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इनके बीच में भारतीय भू-भाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम-बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि 'सीमांत गांधी' के रूप में थी और वे 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के एकदम खिलाफ़ थे। संयोग से, उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और 'पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत' को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **The third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. Eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. This decision could not be made by the midnight of 14-15 August. It meant that a large number of people did not know on the day of Independence whether they were in India or in Pakistan. The Partition of these two provinces caused the deepest trauma of Partition.**

➤ तीसरी समस्या और भी विकट थी। 'ब्रिटिश-इंडिया' के मुस्लिम-बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम आबादी वाले थे। एसे में फ़ैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बँटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक यह फ़ैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बँटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ This was related to the fourth and the most intractable of all the problems of partition. This was the problem of 'minorities' on both sides of the border. Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal (and to some extent Delhi and surrounding areas) found themselves trapped. They were to discover that they were undesirable aliens in their own home, in the land where they and their

➤ इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई 'अल्पसंख्यकों' की थी। सीमा के दोनों तरफ 'अल्पसंख्यक' थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भू-भाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से साँसत में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे 'विदेशी' बन गए थे।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack. No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. But very soon the violence went out of control. The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours' notice.**

➤ जैसे ही यह बात साफ़ हुई कि देश का बँटवारा होने वाला है वैसे ही दोनों तरफ़ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू-शुरू में लोग-बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएँ अस्थायी हैं और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन, बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ़ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने-अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें एसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ Consequences of Partition

The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known.

There were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community. Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata became divided into 'communal zones'. Muslims would avoid going into an area where mainly Hindus or Sikhs lived; similarly the Hindus and Sikhs stayed away from areas of

➤ विभाजन के परिणाम

सन् 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव-इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम-बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ **Forced to abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings. Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in 'refugee camps'. They often found unhelpful local administration and police in what was till recently their own country. They travelled to the other side of the new border by all sorts of means, often by foot. Even during this journey they were often attacked, killed or raped. Thousands of women were abducted on both sides of the border.**

➤ लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ़ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अकसर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बरताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ़ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अकसर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हज़ारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **They were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. In many cases women were killed by their own family members to preserve the 'family honour'. Many children were separated from their parents. Those who did manage to cross the border found that they had no home. For lakhs of these 'refugees' the country's freedom meant life in 'refugee camps', for months and sometimes for years.**

➤ उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने 'कुल की इज्जत' बचाने के नाम पर घर की बहू-बेटियों को मार डाला। बहुत-से बच्चे अपने मां-बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी-कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ What also got divided were the financial assets, and things like tables, chairs, typewriters, paper-clips, books and also musical instruments of the police band! The employees of the government and the railways were also 'divided'. Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbours. It is estimated that the Partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between five to ten lakh people were killed in Partition related violence

➤ वित्तीय संपदा के साथ-साथ टेबुल, कुर्सी, टाईपराइटर और पुलिस के वाद्ययंत्रों तक का बँटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बँटवारा हुआ। अब तक साथ-साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सीमा-पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन पाँच से दस लाख लोगों ने अपनी जान गँवाई।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **Beyond the administrative concerns and financial strains, however, the Partition posed another deeper issue. The leaders of the Indian national struggle did not believe in the two-nation theory. And yet, partition on religious basis had taken place. Did that make India a Hindu nation automatically? Even after large scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12 per cent of the total population in 1951.**

➤ प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्वि-राष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल, विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वज़ह से भारत अपने-आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12 फीसदी मुसलमान थे।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ **So, how would the government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities (Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, Parsis and Jews)? The Partition had already created severe conflict between the two communities.**

➤ ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बरताव करे? बँटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ **There were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of the Muslims in colonial India. It was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. Similarly, there were organisations, which were trying to organise the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. But most leaders of the national movement believed that India must treat persons of**

➤ इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की माँग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल, भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **all religions equally and that India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practiced another religion. All citizens would be equal irrespective of their religious affiliation. Being religious or a believer would not be a test of citizenship. They cherished therefore the ideal of a secular nation. This ideal was enshrined in the Indian Constitution.**

➤ वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहाँ किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ Integration of Princely states

British India was divided into what were called the British Indian Provinces and the Princely States. The British Indian Provinces were directly under the control of the British government. On the other hand, several large and small states ruled by princes, called the Princely States, enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. This was called paramountcy or suzerainty of the British crown. Princely States covered one-third of the land area of the British Indian Empire and one out of four Indians lived under princely rule.

➤ रजवाड़ों का विलय

ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ़ छोटे-बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश-राज की अधोनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक-तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक चार भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ The problem

Just before Independence it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over Princely States would also lapse. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. This decision was left not to the people but to the princely rulers of these states. This was a very serious problem and could threaten the very

➤ समस्या

आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी-शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश-प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश-अधोनता से आज़ाद हो जाएँगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े (रजवाड़ों की संख्या 565 थी) ब्रिटिश-राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएँगे। अंग्रेजी-राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मँडरा रहा था।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **The problems started very soon. First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided on Independence. The Nizam of Hyderabad made a similar announcement the next day. Rulers like the Nawab of Bhopal were averse to joining the Constituent Assembly. This response of the rulers of the Princely States meant that after Independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. The prospects of democracy for the people in these states also looked bleak. This was a strange situation, since the Indian Independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. In most of these princely states, governments were run in a non-democratic manner and the rulers were**

➤ **समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने एसी ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान - सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ़ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे-छोटे देशों की शकल में बँट जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय जान पड रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ-साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे।**

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ Government's approach

The interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different sizes. The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the States should be free to adopt any course they liked. Sardar Patel was India's Deputy Prime Minister and the Home Minister during the crucial period immediately following Independence. He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. It may look easy now. But it was a very complicated task which required skilful persuasion. For instance, there were 26 small states in today's Orissa. Saurashtra region of Gujarat had 14 big states, 119 small states and numerous other different

➤ सरकार का नज़रिया

छोटे-बड़े विभिन्न आकार के देशों में बँट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने -समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और व्यक्तिपूर्ण पहलकदमी की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे-छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

The government's approach was guided by three considerations. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian union. Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions. Thirdly, in the backdrop of Partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance

देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी जैसा कि जम्मू-कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की माँगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता-एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **Before 15 August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India, into the Indian Union. The rulers of most of the states signed a document called the 'Instrument of Accession' which meant that their state agreed to become a part of the Union of India. Accession of the Princely States of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. The issue of Junagarh was resolved after a plebiscite confirmed people's desire to join India. You will read about Kashmir in Chapter**

➤ शांतिपूर्ण बातचीत के ज़रिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएँ आज़ाद हिंदुस्तान की नयी सीमाओं से मिलती थीं, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति-पत्र को 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां



Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ Hyderabad

Hyderabad, the largest of the Princely States was surrounded entirely by Indian territory. Some parts of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Its ruler carried the title, 'Nizam', and he was one of the world's richest men. The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were

➤ हैदराबाद

हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्रप्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को 'निज़ाम' कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निज़ाम ने सन् 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता एक साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ In the meantime, a movement of the people of Hyderabad State against the Nizam's rule gathered force. The peasantry in the Telangana region in particular, was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. Women who had seen the worst of this oppression joined the movement in large numbers. Hyderabad town was the nerve centre of this movement. The Communists and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement. The Nizam responded by unleashing a para-military force known as

➤ इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ़ एक आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ़ उठ खड़े हुए। महिलाएँ निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थीं। महिलाएँ भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ीं। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ़ एक अर्द्ध-सैनिक बल रवाना किया।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **The atrocities and communal nature of the Razakars knew no bounds. They murdered, maimed, raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. The central government had to order the army to tackle the situation. In September 1948, Indian army moved in to control the Nizam's forces. After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. This led to Hyderabad's accession to India.**

➤ इसे रज़ाकार कहा जाता था। रज़ाकार अब्बल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रज़ाकारों ने गैर-मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया। रज़ाकारों ने लूटपाट मचायी और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना, निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुँची। कुछ रोज तक रुक-रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ Manipur

A few days before Independence, the Maharaja of Manipur, Bodhachandra Singh, signed the Instrument of Accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948 and the state became a constitutional monarchy. Thus Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise.

➤ मणिपुर

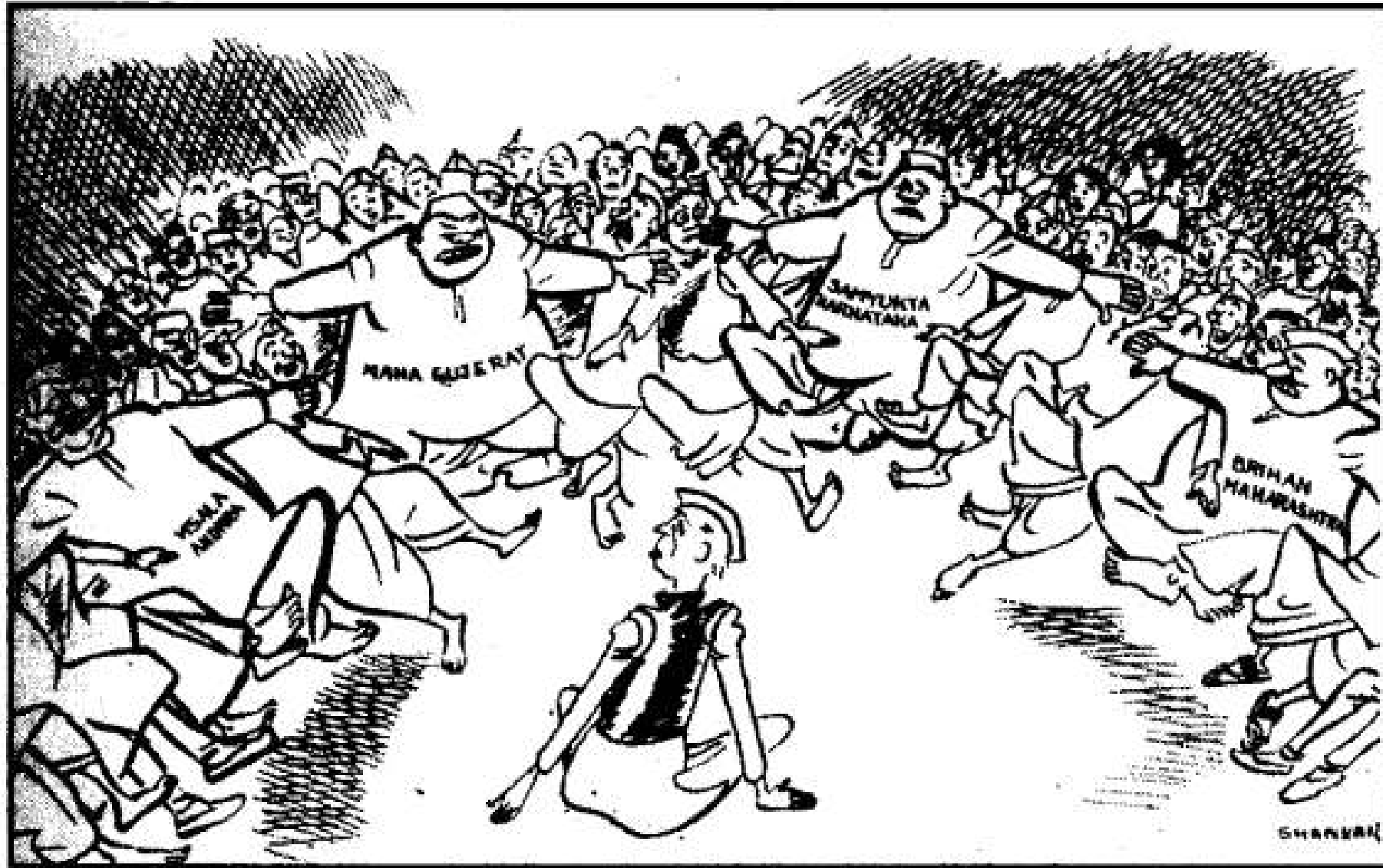
आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ In the Legislative Assembly of Manipur there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. While the state Congress wanted the merger, other political parties were opposed to this. The Government of India succeeded in pressurising the Maharaja into signing a Merger Agreement in September 1949, without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. This caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt.

➤ मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ



“Struggle for Survival” (26 July 1953) captures contemporary impression of the demand for linguistic states

‘स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल’ (26 जुलाई 1953) शीर्षक यह कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की माँग ज़ोर पकड़ रही थी।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ Reorganisation of States

The process of nation-building did not come to an end with Partition and integration of Princely States. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. This was not just a matter of administrative divisions. The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation.

➤ राज्यों का पुनर्गठन

बँटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers.**

➤ औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थीं या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states. In fact after the Nagpur session of Congress in 1920 the principle was recognised as the basis of the reorganisation of the Indian National Congress party itself. Many Provincial Congress Committees were created by linguistic zones, which did not follow the administrative divisions of British India.**

➤ हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन् 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल, इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस-समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियाँ ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थीं।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **Things changed after Independence and Partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. The central leadership decided to postpone matters. The need for postponement was also felt because the fate of the Princely States had not been decided. Also, the memory of Partition was still fresh.**

➤ आज्ञादी और बँटवारे के बाद स्थितियाँ बदलीं। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था। बँटवारे की यादें अभी ताज़ा थी

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **This decision of the national leadership was challenged by the local leaders and the people. Protests began in the Telugu speaking areas of the old Madras province, which included present day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. The Vishalandhra movement (as the movement for a separate Andhra was called) demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. Nearly all the political forces in the Andhra region were in favour of linguistic reorganisation of the then**

➤ केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र आंदोलन (आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन) ने माँग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगुभाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु-भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थीं।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **The movement gathered momentum as a result of the Central government's vacillation. Potti Sriramulu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. This caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large numbers took to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952.**

➤ केंद्र सरकार 'हां-ना' की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधोवादी, पोट्टी श्रीरामुलु, अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह-जगह हिंसक घटनाएँ हुईं। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **The formation of Andhra spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. These struggles forced the Central Government into appointing a States Reorganisation Commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of states. The Commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. On the basis of its report the States Reorganisation Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 states and six union territories.**

➤ आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश बनाए गए।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **One of the most important concerns in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of the country. It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation. But the leadership, under popular pressure, finally made a choice in favour of linguistic states. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic**

➤ आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की माँग से देश की एकता पर आँच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नव-निर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकर नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बँटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय माँगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

➤ **Now it is more than fifty years since the formation of linguistic states. We can say that linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. The path to politics and power was now open to people other than the small English speaking elite. Linguistic reorganisation also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. It did not lead to disintegration of the country as many had feared earlier. On the contrary it strengthened national unity**

➤ भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे-से अंग्रेजीभाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मज़बूत हुई।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां

➤ Above all, the linguistic states underlined the acceptance of the principle of diversity. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. The choice was larger than that. It was a choice in favour of recognising and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and ways of life. Much of the

➤ सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा-सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक वृहत्तर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। साथ ही, यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन-पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली।

Challenges of Nation Building राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां



“Coaxing the Genie back” (5 February 1956) asked if the State Reorganisation Commission could contain the genie of linguism.

‘कोक्सिंग द जेनी’ (5 फरवरी, 1956) शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया है।